हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 130 लखनऊ मंगलवार 30 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

सीएम योगी बोले- हर मंडल मुख्यालय पर बनाएंगे स्पोर्ट्स कॉलेज

इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रही सरकार

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिले स्तर पर बड़ा स्टेडियम बनवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ सरकार हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है। बेलीपार के पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। रीजनल स्टेडियम का भी 63 करोड़ रुपये की लागत से नवोद्धार हो रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में भी बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी का विश्व स्तरीय निर्माण जारी है। अब सरकार की तैयारी हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह जल्द ही गोरखपुर महानगर की सभी संस्थाओं के साथ बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में संस्थाओं का आह्वान किया जाएगा कि वे एक–एक खेल को गोद लें। कुछ सहयोग वे करें और कुछ सरकार करेगी। यहां पर अच्छे कोच रखे जाएंगे। इससे बच्चों को खेल के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म प्राप्त होगा। अगली बार कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी होंगी प्रतियोगिताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक खेल स्पर्धा को लेकर अपनी आगामी योजना भी साझा की। उन्होंने कहा कि अगली बार बच्चों और छात्रों के स्तर के साथ ही वार्ड स्तर पर कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वार्ड स्तर, उसके बाद कुछ वार्डों को मिलाकर उपनगरीय और फिर नगर स्तर पर बड़ी प्रतियोगिता, बड़े समारोह का आयोजन कर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों–छात्रों की प्रतियोगिताएं बालक व बालिका वर्ग में तीन स्तर, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी कहा गया है। कला के अलग अलग विधाओं गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि की यह प्रतियोगिता जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी। 11 से 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के मुख्य

आयोजन में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। खेलेगा युवा तो खिलेगा देश सीएम योगी ने खेलकूद के महत्व को समझाते हुए कहा कि युवा खेलेगा तो देश खिलेगा। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलताओं का मार्ग स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। 11 वर्ष में खेल के क्षेत्र में हुआ भारी परिवर्तन मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष के अंदर देश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चौंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा की एक नई मांग खड़ी हो चुकी है और इसी को ध्यान में रख करके सरकार स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रही है। भीषण ठंड में खिलाड़ियों के उत्साह को सीएम से सराहा मुख्यमंत्री ने भीषण ठंड में भी खिलाड़ियों के उत्साह की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विधायक खेल स्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से 1000 और अप्रत्यक्ष रूप से 10000 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है। विधायक खेल स्पर्धा 2025 में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबाल, जूडो और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है और हमें शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से चुस्त–दुरुस्त बनाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। सीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह विधायक खेल स्पर्धा के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुश्ती (74 किग्रा भारवर्ग) और कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखा। खिलाड़ियों के दांव और मूवमेंट को गहनता से देखते हुए उन्होंने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता शुभम यादव, उप विजेता अनुराग यादव तथा सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम व उप विजेता टीम नीना थापा के खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और उपहार देकर पुरस्कृत किया।

एससी से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी। उसने कहा कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के

कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं। उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। सेंगर ने इस मामले में दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। बहरहाल भाजपा से निष्कासित नेता जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है। बलात्कार का मामला और इससे जुड़े अन्य मामले अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे।

अरावली मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मांगा इस्तीफा

एजेंसी/नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा से जुड़े मामले पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि अब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए जो नई परिभाषा की बार–बार वकालत कर रहे थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार अरावली को बचाने का नहीं , बेचने का प्रयास कर रही है। रमेश ने कहा , "कांग्रेस उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से परिभाषा बदलने की कोशिश की गई थी, उसका मकसद सिर्फ खनन की गतिविधियों, रियल स्टेट को बढ़ावा देना था।

संक्षिप्त समाचार

2026–27 के बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी दिखेगा अमेरिका के टैरिफ का असर

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी बजट पर विचार– विमर्श करने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र विशेषज्ञों से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं और भारत के निर्यात पर अमेरिका के 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बीच यह बजट पेश किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम और आयोग के अन्य सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे।

कैप्टन की हत्या का आरोपी भगोड़ा UAE से लाया जाएगा वापस, प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। कैप्टन विर्दी हत्याकांड के भगोड़े हुसैन मोहम्मद शत्ताफ को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात

के साथ भगोड़े शत्ताफ उर्फ हुसैन महबूब खोखावाला के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शत्ताफ महाराष्ट्र के लोनावला में 2006 में सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी की हत्या के मामले में वांछित है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्यर्पण का अनुरोध पिछले सप्ताह यूएई स्थित भारतीय दूतावास को भेज दिया गया था, माना जाता है कि शत्ताफ जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रह रहा है। जल्द ही भारत लाया जाएगा भगोड़ा हुसैन विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार ने यूएई से भगोड़े को प्रत्यर्पित करने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत वांछित अपराधियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। शत्ताफ पर हत्या के आरोपों के साथ–साथ जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और फर्जी जानकारी के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के अलग–अलग मामले भी दर्ज हैं। आरोप है कि अपराध के बाद वह भारत से भाग गया। संयुक्त अरब अमीरात में रहने के लिए उसने विवाह प्रमाण पत्र में जालसाजी की। उसका भारतीय पासपोर्ट, जो 2019 में जारी किया गया था, 2021 में समाप्त हो गया था। क्या था कैप्टन विर्दी हत्याकांड? 19 साल पहले 14 मई 2006 को पुणे के मशहूर हिल स्टेशन लोनावला में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी के बंगले पर उनकी खून से सनी लाश बरामद हुई थी। हत्यारों ने शातिराना तरीके से हत्या को अंजाम दिया था, जिससे पुलिस के हाथ कोई सुराग न लगे। पुलिस की शुरुआत जांच में मामला लूटपाट के दौरान हत्या का लगा। हालांकि, जांच आगे बढ़ने के साथ कई राज खुले। जांच में हुसैन मोहम्मद शत्ताफ, उसकी पत्नी वाहीदा हुसैन शत्ताफ और उनके एक सहयोगी जानिश खान का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि, हुसैन शत्ताफ और वाहीदा कानून की पेचीदगियों का फायदा उठा कर बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत पाने में सफल रहे। कोर्ट ने शत्ताफ और उसकी पत्नी को बरी कर दिया. इसी के बाद मुख्य आरोपी हुसैन मोहम्मद शत्ताफ भारत छोड़कर यूएई फरार हो गया. हालांकि, अब उसे वापस भारत लाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

120 किमी की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। डीआरडीओ ने सोमवार को 120 किमी की मारक क्षमता वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट का पहला सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ और अन्य हितधारकों को बधाई दी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (MBRL) ने भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति को नई धार दी है। 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ यह भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता का प्रमुख आधार बनेगा। यह प्रणाली न सिर्फ लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है, बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुरूप कई उन्नत खूबियों से भी लैस है। स्वदेशी प्रणाली ने दुनिया के आधुनिक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम से ली टक्कर पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने किया है, जबकि इसके निर्माण और आपूर्ति में भारतीय रक्षा उद्योग की अहम भागीदारी रही है। यह पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मजबूती देती है। पिनाका का शुरुआती संस्करण लगभग 40 किलोमीटर की रेंज तक सीमित था, लेकिन तकनीकी सुधारों के साथ इसकी मारक क्षमता पहले 60 और 75 किलोमीटर तक बढ़ाई

गई। अब 120 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण इसे दुनिया की आधुनिक रॉकेट आर्टिलरी प्रणालियों की कतार में खड़ा करता है। पिनाका रॉकेट की प्रमुख खूबियां 120 किमी रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स में उन्नत गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे यह अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकते हैं। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) और सैटेलाइट आधारित मार्गदर्शन तकनीक का उपयोग किया गया है, जो लक्ष्य से विचलन को न्यूनतम करता है। इसके कारण कोलेटरल डैमेज कम होता है और प्रभावशीलता बढ़ती है। पिनाका रॉकेट की एक बड़ी खासियत इसकी तेज फायरिंग क्षमता है। एक लॉन्चर से कुछ ही सेकंड में कई रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिससे दुश्मन के बड़े इलाके को कम समय में कवर किया जा सकता है। इसे 'शूट एंड स्कूट' क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, यानी फायरिंग के तुरंत बाद लॉन्चर अपनी स्थिति बदल सकता है, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचाव होता है। इन रॉकेट्स में विभिन्न प्रकार के वारहेड विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे हाई एक्सप्लोसिव, प्री–फ्रैगमेंटेड और एरिया सैचुरेशन वारहेड। इससे दुश्मन के बंकर, सैन्य ठिकाने, लॉजिस्टिक बेस, रनवे और बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। हर मौसम और हर इलाके में प्रभावी पिनाका सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रेगिस्तान, पहाड़ी और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। यह दिन–रात और हर मौसम में संचालन में सक्षम है। पिनाका लॉन्चर को व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिससे इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है और इसे तेजी से किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। कम समय में रीलोडिंग की सुविधा इसे निरंतर अभियान के लिए उपयोगी बनाती है। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा भारतीय सेना पहले ही पिनाका रॉकेट रेजीमेंट्स को अपनी आर्टिलरी यूनिट्स में शामिल कर चुकी है। 120 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण सेना को दुश्मन के गहराई में स्थित ठिकानों पर भी सटीक प्रहार की क्षमता देगा। इससे न केवल सामरिक बढ़त मिलेगी, बल्कि डिटरेंस क्षमता भी मजबूत होगी।

असम चुनाव से पहले अमित साह ने उठाया घुसपैठ का मुद्दा, बोले– एक मौका और दें हर घुसपैठिया होगा बाहर

एजेंसी

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम की जनता को संबोधित करते हुए आह्वान किया। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग सोच–समझकर करें। शाह ने चुनावों को लेकर कहा कि जनता को एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो राज्य में घुसपैठ की समस्या के खिलाफ सख्ती से काम करे और असम के विकास को प्राथमिकता दे। गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने दावा किया कि असम ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। उन्होंने कहा श्राज्य में पिछले दस वर्षों से चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के ग्यारह वर्षों के कार्यकाल में

असम ने अभूतपूर्व प्रगति की है। यहां 5,000 सीटों वाले सभागार का उद्घाटन करने के बाद शाह ने कहा, अगले साल मार्च–अप्रैल में होने वाले चुनावों में ऐसी सरकार चुनें जो घुसपैठ न होने दे और असम की उन्नति के लिए कार्य करे। उन्होंने आगे कहा, पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकारों के नेतृत्व में असम में बहुत विकास हुआ है। भाजपा को पांच वर्ष का आशीर्वाद और दें, हर घुसपैठिए की पहचान करके उसे वापस भेज दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य में घुसपैठ की समस्या के लिए उसे दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया, श्वोटों के लालच में कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिसने आज असम की पहचान के लिए खतरा पैदा कर दिया है। शाह ने जोर देकर कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अब राज्य के श्सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरणश के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जिस ज्योति–बिष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वह राज्य के विकास का प्रतीक है।

केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बदली जांच समिति

रेजिडेंट पर लगा था ये आरोप...दो नए सदस्य हुए शामिल

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में धर्मांतरण प्रयास के मामले में गठित समिति में बदलाव कर दिया गया है। अब इस समिति में एक महिला डॉक्टर और एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को भी रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद के साथ हुई बैठक के बाद इसका आदेश जारी किया है। केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने धर्मांतरण प्रयास के मामले में बनी जांच समिति में अब प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल के साथ ही सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार को भी शामिल कर लिया है। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। प्रवक्ता के मुताबिक

केजीएमयू प्रशासन की ओर से जांच समिति की सोमवार को बैठक भी हुई। जांच समिति ने विश्व हिंदू परिषद के उस आरोप को गलत पाया जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों में ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के होने की बात कही गई है। जांच में पता चला कि आउटसोर्सिंग पर तैनात 3995 कर्मियों में से सिर्फ 289 ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इसी तरह पैथोलॉजी विभाग में संविदा के आधार पर कुल 51 शिक्षक हैं। इनमें से महज दो ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इसी तरह पीपीपी मॉडल पर काम कर रही एजेंसी के भी 174 कर्मियों में से महज 25 ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। बयान जारी करने लिए भी बनाई गई समिति केजीएमयू प्रशासन ने धर्मांतरण संबंधी मामले पर बयान जारी करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति में पैरामेडिकल संकाय के डीन प्रो. केके सिंह, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल और प्रॉक्टर प्रो. आरएएस कुशवाहा शामिल हैं। इनके अलावा धर्मांतरण संबंधी मामले पर किसी भी शिक्षक को बयान देने से मना किया गया है। ईमेल पर करें धर्मांतरण संबंधी मामलों की शिकायत केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में धर्मांतरण संबंधी किसी भी मामले की शिकायत के लिए ईमेल जारी की है। इस ईमेल पर सीधे समिति के पास अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। यह ईमेल आईडी– factfindingcommittee / kgmcindia-edu है। इस पर परिसर के साथ ही आम जनता भी धर्मांतरण संबंधी मामलों में सूचना दे सकती है।

संपादकीय

भारत के लिए बेअसर रहा ट्रंप का टैरिफ

हाँ, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत के कई निर्यात उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाया था, जिसका मुख्य कारण भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना था, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने बाजार विविधीकरण और उत्पादों में विविधता लाकर इस झटके का सामना किया और निर्यात को बनाए रखा, जिससे 2026 में भी निर्यात में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2025 में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया. उसके बाद भी भारत के एक्सपोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को पानी पानी पिला दिया और भारतीय निर्यातकों ने अपने बाजारों को डायवर्सिफाई करके निर्यात वृद्धि को मजबूती से बनाए रखा. जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को जितने नुकसान होने की संभावना थी वो नहीं हुआ है. इसके विपरीत तेजी देखने को मिली है. जिसका प्रमुख कारण भारत की लंबे समय से की जा रही तैयारी और दुनिया के दूसरे बाजारों में भारत की एक्सेप्टेंस है। इसी से इस बॉत का अनुमान है कि भारत के निर्यात में 2026 में मजबूत वृद्धि होने की पूरी संभावना है। ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ नए व्यापार समझौतों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2025 लगभग बीत रहा है ऐसे में अमेरिकी टैरिफ के बावजूद, 2025 में अमेरिका को निर्यात में भारी वृद्धि हुई। जो भारत की कूटनीति और व्यापार नीति का प्रमाण कही जा सकती है। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में यह वृद्धि सबसे अधिक रही। यह तेजी 2026 में भी जारी रहने की संभावना है. व्यापार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में, व्यापार पानी की तरह है, यह अपना मार्ग खुद ढूंढ लेता है. इसी सिद्धांत के साथ भारतीय वस्तु निर्यात ने कोविड–19 महामारी, रूस–यूक्रेन युद्ध, इजराइल–हमास युद्ध, लाल समुद्र शिपिंग संकट, सेमीकंडक्टर आपूर्ति समस्या और अब अमेरिका के उच्च शुल्क जैसी चुनौतियों के बीच भी तेजी से प्रतिक्रिया दी है। ज्ञात हो कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस तारीख के बाद बहुत से देशों के अमेरिका से संबंधा खराब होना शुरू हो गए थे। उनमें से एक भारत भी था। सत्ता में आते ही ट्रंप के तेवर पहले ही दिन से पूरी दुनिया को समझ में आ गए थे। टैरिफ की रट लगाने वाले ट्रंप आज इस मुद्दे पर बहुत कम ही बोलते हैं। वह चौतरफा घिर चुके हैं। भारत ने उनके टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब दिया।अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट के नुकसान की भरपाई करने और साथ ही भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, भारत ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर्स की तलाश कर रहा है। 2025 में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए।भारत–यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और आर्थिक साझेदारी समझौता मार्च 2024 में साइन किया गया था। यह आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2025 को चार सदस्य देशोंरू आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ लागू हुआ। यही नही भारत रूस के साथ अपनी ऐतिहासिक पार्टनरशिप और चीन के साथ हाल ही में बेहतर हुए संबंधों का भी फायदा उठा रहा है ताकि एक्सपोर्ट के मौके तलाशे जा सकें और इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया जा सके। अमेरिकी टैरिफ के नेगेटिव असर का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति ने महत्वपूर्ण गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सुधारों के जरिए अपनी मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी और लंबे समय तक गिरावट देखी गई। रुपया लगातार नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचता रहा। यह करेंसी, जो साल की शुरुआत में लगभग 85.64 प्रति डॉलर पर थी, दिसंबर की शुरुआत में मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 90 के निशान को पार कर गई और दिसंबर के मध्य तक ध्91 के निशान को भी पार कर गई। सरकार ने इसे जानबूझकर नहीं रोका। लेकिन जब लगा रोकना जरूर तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें दखल दिया। विशेषज्ञों की माने तो कमजोर रुपया चुपचाप भारत की एक्सपोर्ट कमाई को बढ़ाता है। यह बात अब और भी मायने रखती है, क्योंकि ज्यादा टैरिफ और राजनीतिक तनाव के कारण ग्लोबल ट्रेड मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका ने कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, लेकिन कमजोर रुपये ने इसके असर को कम कर दिया है। ज्ञात हो कि न्यूजीलैंड के साथ व्यापार अगले पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। भारत का निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर हो गया था. 2023 में यह गिरकर 389.5 अरब डॉलर रहा, लेकिन फिर 2024 में यह 443 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2025 (जनवरी–नवंबर) तक इसका आंकड़ा लगभग 407 अरब डॉलर हो चुका है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का माल और सेवा निर्यात ऐतिहासिक उच्च स्तर 825.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर छह प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल–नवंबर 2025) में भी निर्यात 562 अरब डॉलर रहा।

पेंशन का सवाल : नेता और विधायक मालामाल, जनता और कर्मचारी बेहाल

— डॉ सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र की किताबों में लिखा है कि सत्ता जनता की सेवक होती है। व्यवहार में यह वाक्य अब एक पुराना मुहावरा बन चुका हैकृइतना पुराना कि सत्ता खुद भी इसे गंभीरता से नहीं लेती। आज का लोकतंत्र सेवा नहीं, सुविधा का तंत्र बन चुका है; और इस तंत्र की सबसे सुंदर, सबसे सुविधाजनक, सबसे सुरक्षित जगह हैकृसर्वसम्मति। जैसे ही बात अपने हितों की आती है, हमारे जनप्रतिनिधि वैचारिक मतभेद भूल जाते हैं। न पक्ष रहता है, न विपक्ष। न सत्ता होती है, न प्रतिपक्ष। सब एक साथ हो जाते हैंकृजैसे कोई पारिवारिक मामला हो, जैसे कोई निजी उत्सव हो। पूर्व विधायकों के लिए ध10,000 यात्रा भत्ता का सर्वसम्मति से पारित होना कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह उस मानसिकता का उद्घाटन है जिसमें सत्ता खुद को जनता से ऊपर और अलग मानने लगती है। यह वही सदन है जहाँ किसानों की आत्महत्याओं पर बहस "असंवेदनशील" हो जाती है, मज़दूरों की मौतें "आँकड़ों" में बदल जाती हैं, बेरोज़गारी "वैश्विक चुनौती" बन जाती है और महँगाई "अस्थायी स्थिति" कहकर टाल दी जाती है। लेकिन जैसे ही बात विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों या सत्ता से जुड़े वर्ग की आती हैकृ लोकतंत्र चौकन्ना हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तत्पर हो जाता है। ध10,000 कोई बड़ी राशि नहीं हैकृयह तर्क अक्सर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह बड़ी राशि नहीं है। लेकिन सवाल राशि का नहीं, नियत का है। सवाल यह है कि जब एक आम कर्मचारी 30द35 साल सेवा देने के बाद भी पेंशन के लिए दर–दर भटकता है, जब लाखों कर्मचारी नई पेंशन योजना के जाल में फँसकर बुढ़ापे की सुरक्षा से वंचित हैं, तब सत्ता से जुड़े लोगों को एक से अधिक पेंशन किस नैतिक अधिकार से मिलती है? यह कैसी व्यवस्था है जहाँ विधायक बनने के पाँच साल बाद भी पेंशन का अधिकार जन्म ले लेता है, लेकिन शिक्षक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, फील्ड वर्करकृजो 60 साल तक सेवा देता हैकृवह पेंशन का पात्र भी नहीं बन पाता? क्या लोकतंत्र में श्रम का मूल्य सत्ता की दूरी से तय होता है? विडंबना यह है कि जिन पूर्व विधायकों को आज यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, वे पहले से ही कई–कई पेंशन ले रहे हैंकृ कभी विधायक की, कभी सांसद की, कभी मंत्री की, कभी समिति की। सत्ता में बिताए गए कुछ वर्षों ने उन्हें आजीवन सुरक्षा दे दी, जबकि वही सत्ता व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में भी असुरक्षित छोड़ देती है। जनता से बार–बार कहा जाता है कि "सरकार के पास पैसा नहीं है।" लेकिन यह वाक्य केवल जनता के लिए आरक्षित है। कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, छात्रों के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। लेकिन नेताओं की सुविधाओं के लिए पैसा हमेशा उपलब्ध रहता हैकृबिना बहस, बिना विरोध, बिना शर्म। सवाल यह भी है कि विरोध आखिर जाता कहाँ है? जिन सदनों में पानी की बोतल पर हंगामा हो जाता है, जहाँ शब्दों पर माइक टूट जाते हैं, जहाँ तख्तियाँ और पोस्टर लोकतंत्र का पर्याय बन जाते हैंकृवहीं इस फैसले पर पूर्ण शांति कैसे छा जाती है? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सुविधाओं के मुद्दे राजनीति से ऊपर हैं? यह वह अघोषित समझौता है, जिसके बारे में जनता को कभी बताया नहीं जाता। चुनाव के समय दल एक–दूसरे के खिलाफ ज़हर उगलते हैं, लेकिन सत्ता के लाभों के समय सभी ज़हर मीठे शरबत में बदल जाते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, सुविधातंत्र है। सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब इस सबको "कानूनी" कहकर जायज़ ठहराया जाता है। हाँ, यह सब कानूनी है। लेकिन क्या हर कानूनी चीज़ नैतिक भी होती है? इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े अन्याय कानून की छाया में ही हुए हैं। अगर कानून जनता की कीमत पर सत्ता की सुविधा सुनिश्चित करे, तो उस कानून पर सवाल उठाना नागरिक कर्तव्य बन जाता है। आज देश का कर्मचारी वर्ग सबसे ठगा हुआ वर्ग है। नई पेंशन योजना के नाम पर उसकी सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई। 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद भी उसे यह भरोसा नहीं कि बुढ़ापे में दवा, इलाज और सम्मानजनक जीवन मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर, सत्ता से जुड़े लोग पेंशन को अधिकार नहीं, विशेषाधिकार बना चुके हैंकृऔर उस विशेषाधिकार पर किसी तरह का आत्मसंयम दिखाना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता नहीं, नैतिक दिवालियापन की निशानी है। जब सत्ता खुद के लिए संवेदनशील और जनता के लिए कठोर हो जाए, तब लोकतंत्र केवल एक शब्द रह जाता हैकृएक खोखला शब्द। आज जनता को बार–बार यह एहसास कराया जा रहा है कि सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है, असहमति अराजकता है और विरोध अनुशासनहीनता। लेकिन सत्ता की सुविधाओं पर चुप्पी ही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि यह चुप्पी उस असमानता को मजबूत करती है, जो समाज को भीतर से खोखला कर देती है। पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते पर सर्वसम्मति कोई उपलब्धि नहीं है। यह उस सोच का प्रमाण है जिसमें सत्ता खुद को विशेष वर्ग मान चुकी है। यह निर्णय एक चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र केवल सत्ता के लिए एकमत होता रहा, तो जनता की असहमति एक दिन सर्वसम्मति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर सामने आएगी। इतिहास गवाह हैकृजब शासक वर्ग अपनी सुविधाओं में डूब जाता है और जनता के दुखों से कट जाता है, तब सत्ता स्थायी नहीं रहती। सिंहासन हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन जनता की स्मृति बहुत लंबी होती है। हाँ, आप बधाई के पात्र हैंकृइसलिए नहीं कि आपने कोई महान जनहितकारी निर्णय लिया, बल्कि इसलिए कि आपने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे लोकतंत्र में अपने लिए सर्वसम्मति है, और जनता के लिए प्रतीक्षा। और यह प्रतीक्षा जब बहुत लंबी हो जाती है, तो वह एक दिन सवाल बनती हैकृ और सवाल, इतिहास की सबसे खतरनाक चीज़ होते हैं।

पितृसत्ता की कीमत अदा कर रहे हैं कुंवारे बेटे

जब करोड़ों भी दुल्हन नहीं दिला पाएँ : उत्तर भारत के लिंगानुपात की भयावह सच्चाई

—डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी संबंध नहीं होता, बल्कि वह समाज की सामूहिक चेतना, नैतिकता और सत्ता–संरचना का आईना भी होता है। लेकिन जब अख़बारों की सुर्ख़ियाँ यह बताने लगें कि करोड़ों की संपत्ति, लाखों की मासिक सैलरी और सरकारी नौकरी होने के बावजूद पुरुषों को दुल्हन नहीं मिल रही, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला व्यक्तिगत विफलता का नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और सभ्यतागत संकट का है। पंजाब और हरियाणा जैसे समृद्ध कहे जाने वाले राज्यों से आई यह सच्चाई किसी एक परिवार या वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है, जिसने वर्षों तक बेटियों को जन्म से पहले ही मिटा दिया। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। यह किसी प्राकृतिक आपदा की तरह समाज पर नहीं टूटा, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा गया। अल्ट्रासाउंड मशीनों के दुरुपयोग, दहेज की भूख, वंशवादी अहंकार और तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा ने मिलकर एक ऐसी ज़मीन तैयार की, जहाँ बेटियों का जन्म ही अपराध मान लिया गया। समाज ने यह मान लिया कि बेटा ही भविष्य है और बेटी बोझ। आज उसी सोच की कीमत समाज को सामूहिक रूप से चुकानी पड़ रही है। सरकारी आँकड़े भले यह दावा करें कि लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन विवाह के बाज़ार में दिखाई दे रही सच्चाई इन दावों की पोल खोल देती है। जब हज़ारों आवेदनों में 92 प्रतिशत पुरुष दुल्हन की तलाश में हों, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आँकड़े और ज़मीनी हकीकत के बीच एक गहरी खाई है। यह केवल संख्याओं का सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन का प्रश्न है। लिंगानुपात कोई साधारण जनसांख्यिकीय आँकड़ा नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य का संकेतक होता है। आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके वे पुरुष विवाह के लिए दर–दर भटक रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है, मकान है, गाड़ी है और सम्मानजनक नौकरी भी। वैवाहिक बैठकों में यह कहना कि "तलाक़शुदा चलेगी", "एक बच्चा हो तो भी चलेगा", किसी उदार सोच का नहीं, बल्कि गहरी हताशा का बयान है। यह वही समाज है जिसने कभी लड़की के रंग, रूप, कद और दहेज के आधार पर रिश्ते ठुकराए थे। आज वही समाज चयन से बाहर खड़ा है। पितृसत्ता ने सदियों तक स्त्री को केवल एक वस्तु की तरह देखाकृजिसे परखा जा सकता है, बदला जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आज वही पितृसत्ता अपने ही बनाए ढांचे में फँस गई है। यह उसकी ऐतिहासिक विफलता है कि उसने जिस व्यवस्था को अपने लाभ के लिए खड़ा किया, वही व्यवस्था अब उसके अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ी है। जिन इलाकों में भ्रूण हत्या सबसे अधिक हुई, वहीं आज विवाह संकट सबसे गहरा है। समाज ने सोचा था कि बेटियाँ कम होंगी तो बेटों की क़ीमत बढ़ेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलटकृबेटियाँ कम हुईं और बेटों का भविष्य असुरक्षित हो गया। इस स्थिति के लिए केवल परिवारों को दोष देना आसान है, लेकिन यह अधूरा सच होगा। राज्य, समाज और धर्मकृतीनों इस संकट के सह–निर्माता हैं। प्रशासन ने लिंगानुपात को एक फ़ाइल में दर्ज होने वाला आँकड़ा समझा, संवेदनशील सामाजिक चेतावनी नहीं। राजनीति ने इसे कभी गंभीर चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इससे तात्कालिक वोट नहीं मिलते। धर्म और जाति ने इसे संस्कार और परंपरा के नाम पर ढक दिया, मानो बेटी पैदा करना कोई अपराध हो। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान पोस्टरों, नारों और भाषणों तक सीमित रह गए। ज़मीनी स्तर पर सख़्ती, निरंतर सामाजिक संवाद और वैचारिक संघर्ष की जगह प्रचार ने ले ली। नतीजा यह हुआ कि योजनाएँ चलती रहीं और बेटियाँ घटती रहीं। समाज ने आँख मूँदकर यह मान लिया कि यह समस्या भविष्य की है, आज की नहीं। अब जब भविष्य दरवाज़े पर खड़ा है, तो घबराहट साफ़ दिखाई दे रही है। आज दिखाई दे रहा यह विवाह संकट आने वाले सामाजिक विस्फोट का संकेत है। यदि यही स्थिति बनी रही, तो महिलाओं की ख़रीद–फरोख़्त, ज़बरन विवाह, मानव तस्करी और महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा जैसी घटनाएँ बढ़ेंगी। ये घटनाएँ किसी विकृत मानसिकता के अपवाद नहीं होंगी, बल्कि असंतुलित समाज का स्वाभाविक परिणाम होंगी। जब समाज में स्त्रियों की संख्या घटती है, तो उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ती, बल्कि उनका शोषण नए और अधिक ख़तरनाक रूपों में सामने आता है। यह संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम स्त्री को अब भी केवल पत्नी, बहू और माँ की सीमित भूमिकाओं में ही बाँधकर देखेंगे, या उसे एक स्वतंत्र और बराबरी का नागरिक मानेंगे। जब तक बेटी को शिक्षा, संपत्ति में अधिकार, निर्णय की स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार टिकाऊ नहीं हो सकता। यह समस्या कानून से ज़्यादा मानसिकता की है और मानसिकता बदलने के लिए साहसिक सामाजिक ईमानदारी चाहिए। उत्तर भारत का यह विवाह संकट दरअसल एक आईना हैकृ उस समाज के लिए, जिसने बेटियों को जन्म से पहले मिटा दिया और आज दुल्हन के लिए तरस रहा है। यह केवल अविवाहित पुरुषों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नैतिक हार है। जिस समाज ने स्त्री को बोझ समझा, वही समाज आज अपने ही बेटों का भविष्य ढो रहा है। अब भी समय है, लेकिन समाधान आँकड़ों, अभियानों और नारों से नहीं आएगा। इसकी शुरुआत सोच बदलने से ही होगी।

राहुल-खड़गे को सावधान होने की जरूरत

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपनी स्थापना के 140 साल पूरे किए। एक संगठन, एक राजनैतिक दल के तौर पर तमाम उतार–चढ़ावों के बीच इतना लंबा सफर तय करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। जिसमें वक्त के अनुसार तरीके बदलते रहे। कांग्रेस के भीतर अलग विचारधाराएं पनपीं, जिनके कारण कई बार पार्टी में टूट हुई। कांग्रेस से निकले लोगों ने अपने नए दल बनाए, कभी उन दलों का कांग्रेस में विलय हुआ, कभी वे साथ चलते रहे। कांग्रेस ने कई बार भितरघात भी सहे। लेकिन इन सबके बीच कभी भी अपनी मूल विचारधारा को नहीं छोड़ा, जो असल में भारत की उदार और समावेशी संस्कृति से निकली है। जिसमें किसी भी किस्म के भेदभाव, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा के लिए जगह नहीं है। उच्च नैतिक आदर्शों के साथ अस्तित्व को कायम रखना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस इस कसौटी पर खरी उतरती आई है।स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उन्हें साफ संदेश है कि पार्टी भले सत्ता में न हो, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न कभी संविधान से समझौता किया, न धर्मनिरपेक्षता से और न ही लोगों के अधिकारों से। श्री खड़गे ने साफ कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। आज जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं, कांग्रेस उसी भारत के लिए संघर्ष जारी रखेगी, जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश की आत्मा और संविधान को बचाने की है।इसी तरह राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज के कमजोर, वंचित और मेहनतकश वर्ग के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस का संकल्प नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई को और मजबूत करने का है। यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को बचाने के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के संघर्ष को जारी रखने का जो आह्वान किया है, उसमें एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा से बाहर निकालने और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया है, वहीं दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को इशारे से जवाब भी दिया गया है कि सत्ता रहे न रहे लेकिन रीढ़ सीधी होनी चाहिए यानी आत्मसम्मान बना रहना चाहिए, जिसमें कांग्रेस अब तक सफल रही है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को लालकृष्ण आडवानी और नरेन्द्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा और संघ के संगठन की तारीफ की, कि जमीन पर बैठने वाला एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया। इस तस्वीर में आडवानी सोफे पर बैठे हैं और नरेन्द्र मोदी जमीन पर।दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सवाल उठने लगे कि क्या श्री सिंह अब भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं या ये राज्यसभा में फिर से आने की भूमिका बांधी गई है। दिग्विजय सिंह ने क्या राहुल गांधी और कांग्रेस में गांधी परिवार के रसूख पर हमला बोला है, ये कयास भी लगे। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है और कहा जी हां मैं भी यही चाहता हूं कि पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएश्। हमारा 140 साल का इतिहास है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम खुद से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब जानते हैं कि कांग्रेस में जहां अध्यक्ष का बाकायदा चुनाव होता है, वहीं भाजपा में अंदरूनी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पहले से टू मच डेमोक्रेसी की पहचान करते हुए एक किस्म की तानाशाही बनी हुई है। पार्टी का संविधान कुछ भी कहे, भाजपा में आज की तारीख में वही होता है, जो नरेन्द्र मोदी और अमित शाह तय करते हैं। चाहे दिग्गज नेताओं को एक झटके में किनारे करते हुए कम पहचाने चेहरों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो या जब मन चाहे मुख्यमंत्री समेत पूरी केबिनेट बदलना हो या रातों रात किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना हो और अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उसे एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देना हो, मोदी–शाह की जोड़ी ही सारे फैसले लेती है और इसमें किसी जमीन पर बैठने वाले कार्यकर्ता की बात तो दूर, कई सालों से सांसद और विधायक बनने वाले वरिष्ठ नेता भी हूं चूं नहीं कर पाते। जिन लालकृष्ण आडवानी के सामने नरेन्द्र मोदी जमीन पर बैठे थे, उन्हीं आडवानी को कैसे कई मौकों पर मोदी ने बेइज्जत किया है, ये भी दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने देखा ही है। फिर भी उन्हें भाजपा और संघ से प्रेरित होना हो, तो इसमें अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सावधान होने की जरूरत है। भाजपा तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कहती आई। उसमें सफल नहीं हो पाई तो कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाकर उसके कई नेताओं को भगवा गमछा ओढ़ा दिया। राहुल गांधी ने तब भी कहा कि अच्छा है हमारे यहां सफाई हो गई। अभी लोकसभा हारने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार भी कांग्रेस हारी, लेकिन फिर भी उतने ही दम से कांग्रेस भाजपा को मनरेगा खत्म करने से लेकर अरावली में खनन और एसआईआर की गड़बड़ियों पर चुनौती दे रही है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की जमीनी ताकत भाजपा ने देखी है और अब 5 जनवरी से मनरेगा बचाने के लिए फिर से कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत कर रही है। इन सबसे भाजपा को यह समझ आ रहा है कि कांग्रेस को दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता की नहीं, विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और इस देश की जनता की आत्मा है। इसलिए दिग्विजिय सिंह जैसे नेताओं के बयानों में भाजपा अपने लिए अवसर तलाशती है। अब श्री सिंह भले कहें कि वो संघ की विचारधारा के खिलाफ हैं और केवल संगठन की तारीफ कर रहे थे। लेकिन सवाल तो बना हुआ है कि आपने तारीफ के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक का अहम दिन ही क्यों चुना। क्यों पार्टी की स्थापना दिवस से एक दिन पहले अनावश्यक विवाद खड़ा किया।

राशिफल

मेष :– भौतिक आकांक्षाएं सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुन्दर छबि बनावें।

बृषभ :– नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य पूर्ण होने के आसार हैं। पुराने संबंधों से लाभ संभव। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता हेतु मन चिंतित होगा।

मिथुन :– विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। अच्छी भावनात्मक अभिब्यक्ति से संबंध मधुर बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता बरतें।

कर्क :– भावनात्मक सहयोग से मन उत्साहित होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में मनोवान्छित सफलता मिलने के आसार हैं। मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित होगा। रोजगार में अति व्यस्तता रहेगी।

सिंह :– कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

कन्या :– भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय संभव। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे अपयश या लान्छन मिले।

तुला :– निकट संबंधो में भावनात्मक सहयोग से मन उत्साहित होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में मनोवान्छित सफलता मिलने के आसार हैं। संतान संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व अपनी पूर्ति हेतु दवाब बनाएंगे।।

वृश्चिक :– परिवार में कोई सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी। कार्यक्षेत्र में संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। ग्रहों की अनुकूलता से कोई अवरोधित कार्य हल होने के आसार बनेंगे। घर में खुशहाली रहेगी।

धनु :– कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होंगी। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें।

मकर :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मन पर प्रभावी होंगी। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। किसी नये संबंध के प्रति निकटता बढ़ेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

कुंभ :– कुछ नये पारिवारिक तनावों से मन अशांति से प्रभावित रहेगा। कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी। शिक्षार्थी शिक्षा में ध्यान दें। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें।

मीन :– नयी आशाएं नवीन उत्साह का संचार करेंगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें। क्रोध पर काबू रखें और आवेश में कोई निर्णय न लें। घर–परिवार में मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

दोस्ती अखबार से

ऐसे दौर में जब बच्चे डिजिटल मीडिया को अंतिम सत्य मानने लगे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य बनाना एक सुखद अहसास ही है। सुबह की प्रार्थना के दौरान दस मिनट तक राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय खबरें व संपादकीय पढ़ना अनिवार्य किया गया है। बाकायदा रोज पांच कठिन शब्द अर्थ के साथ ब्लैकबोर्ड पर दर्ज होंगे। निश्चय ही इस प्रयास से जहां बच्चों में पढ़ने की संस्कृति, शब्द व सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, वहीं उनके स्क्रीन टाइम में कमी आ सकेगी। निर्विवाद रूप से इससे धीरे–धीरे छात्रों की पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बच्चे पढ़ने की संस्कृति से जुड़कर भावनात्मक, बौद्धिक व सामाजिक सरोकारों से समृद्ध होंगे। बहुत संभव है कि यदि इस अभियान को निरंतरता के साथ चलाया जाता रहा तो बच्चे पुस्तकालयों में रुचि लेने लगेंगे। विडंबना यह है कि आज बच्चों की उंगलियां पुस्तकों के पन्ने पलटने के बजाय मोबाइल के की–बोर्ड पर थिरकती रहती हैं। चिंताजनक स्थिति है कि भारत में पांच साल तक के बच्चे भी रोज दो घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं। एक सर्वे में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि दो साल जैसी कम उम्र के बच्चे भी रोज 1.2 घंटे स्क्रीन पर लगाते हैं। गंभीर स्थिति यह है कि एक चौथाई बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच है। ऐसे वक्त में जब आस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को रोका गया है, भारत में दस साल से कम उम्र के बच्चों तक के सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि मॉर्निंग असेंबली के दौरान बच्चों को अंग्रेजी व हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे। ये निर्णय सभी सरकारी सेकेंडरी और बेसिक स्कूलों के लिये है, लेकिन यदि निजी स्कूल भी चाहें तो वे भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं। निस्संदेह, बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम से अलग भी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि आज भी अखबार भरोसेमंद सूचना माध्यम हैं। कई चरणों में संपादकीय मंडल खबरों को सुरक्षित तरीके से जांच कर प्रकाशित करता है। यूं तो कथित सोशल मीडिया पर सूचनाओं का अंबार लगा है, लेकिन संपादक नामक संस्था के न होने से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। निहित स्वार्थी तत्व भ्रामक सूचनाएं लगातार प्रसारित करते रहते हैं। निस्संदेह, बच्चे जब अखबार पढ़ेंगे तो अखबारों के संपादकीय व लेख पढ़कर वे अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। साथ ही उनकी भाषा समृद्ध होगी। आजकल के छात्रों के सबसे कम नंबर मातृभाषा में ही आते हैं। संकट यह भी है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की मासूमियत छीन रहे हैं और उन्हें समय से पहले वयस्क बना रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में अखबारों के जरिये मिलने वाली प्रामाणिक जानकारी उनकी सकारात्मक सोच को विकसित करेगी। बच्चों की पढ़ने की यह आदत तब और विकसित होगी, जब अभिभावक भी बच्चों को घर में पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। यहां यह भी जरूरी है कि बच्चों के लिये स्कूलों में शुरू हुआ यह अभियान निरंतरता के साथ चलता रहे।

एलडीए ने अमौसी एयरपोर्ट के पीछे 21 अवैध रो-हाउस भवनों पर चलाया बुलडोजर

– एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन–2 की टीम ने की कार्रवाई
– 5 जेसीबी व 1 पुकलैंड मशीन की मदद से 8 घंटे में ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमौसी एयरपोर्ट के पीछे बनी अवैध कालोनी पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान निजी बिल्डर द्वारा कालोनी में बनाये गये 21 रो–हाउस भवनों को जमींदोज कर दिया गया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन–2 की टीम ने की।

प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि बिजनौर थानाक्षेत्र में अमौसी एयरपोर्ट के पीछे बिल्डर राधेश्याम ओझा व अन्य द्वारा लगभग 5,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से कालोनी विकसित करते हुए 21 रो–हाउस भवनों का निर्माण कराया गया था। प्राधिकरण से ले–आउट व मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। इस बीच बिल्डर ने विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय आयुक्त न्यायालय और फिर माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की, जहां से बिल्डर को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने उक्त प्रकरण में तत्काल अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे। जिसके अनुपालन में सोमवार को प्रवर्तन जोन–2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय एवं दिनेश वर्मा समेत टीम ने मौके पर अभियान चलाया। जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि बिल्डर द्वारा स्थल पर 21 रो–हाउस भवनों का निर्माण कराया गया था। करीब 8 घंटे तक चली कार्रवाई में 5 जेसीबी व 1 पुकलैंड की मदद से सभी अवैध रो–हाउस भवनों को ध्वस्त कर दिया गया।

ब्राह्मण विधायको की बैठक अब भाजपा का सिर्फ अंदरूनी मामला नही रहा

बृजेश चतुर्वेदी

लखनऊ। मोदी के सामने डैमेज कंट्रोल की कोशिश लेकर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की कवायद फिलहाल पूरी तरह नाकाम होती दिख रही है। दिल्ली जाकर हालात संभालने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि करीब 50 ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता न सिर्फ कायम है, बल्कि और मजबूत होकर उभर आई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरे देश से पी एन पाठक के पास लगातार फोन आ रहे हैं। अलग–अलग राज्यों से लोग साफ शब्दों में कह रहे हैंकृ "पाठक जी, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते हैं।" यह महज़ समर्थन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। पीएन पाठक को मिलने वाले फोन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर रिटायर्ड जज, वरिष्ठ वकील और डॉक्टर तक खुलकर उनके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। यह संकेत है कि मामला अब सिर्फ पार्टी के भीतर का नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक

वर्गों तक फैल चुका है। आज की तारीख में, जब जाति के नाम पर गैर–ब्राह्मण समुदाय के नेता खुलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, तब भाजपा द्वारा जाति समीकरण साधने के नाम पर चुनाव हारे हुए चेहरे को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उससे जुड़ी चिट्ठी ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। यह कोई मामूली बैठक नहीं थी। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायक एक साथ सामने आए और उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का खुला ऐलान किया। इस घटनाक्रम ने पूरे देश को साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा। वह अब संगठित है, सचेत है और सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखता है। अब सवाल यह नहीं है कि पार्टी नेतृत्व इसे कैसे देखता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या इस संदेश को गंभीरता से लिया जाएगाकृ या फिर इसके राजनीतिक नतीजे आने वाले समय में और बड़े झटके के रूप में सामने आएंगे।

मुंशीपुलिया से एयरपोर्ट जा रही मेट्रो के अचानक ब्रेक फेल, भेजी गई अतिरिक्त मेट्रो; यात्री परेशान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में मुंशीपुलिया से एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो के ब्रेक सोमवार दोपहर फेल हो गए। ब्रेक के काम नहीं करने पर ट्रेन अचानक

रुक गई। हालांकि इससे कोई हादसा नहीं हुआ। यात्रियों को सकुशल उतारकर दूसरी मेट्रो में सवार किया। उधर मेट्रो में गड़बड़ी होने से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टनगर डिपो से दूसरी मेट्रो भेजी गई। मामला सोमवार दोपहर करीब बारह बजे के आसपास का है। मुंशीपुलिया से अमौसी एयरपोर्ट के लिए मेट्रो रवाना हुई। कुछ देरी में ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। लोको पायलटों को इसकी जानकारी होते ही तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इसके बाद यात्रियों को मेट्रो से उतारा गया। साथ ही इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंच गई और मरम्मत कार्य में जुट गई। मेट्रो को रूट से हटाकर डिपो ले जाया गया। दूसरी ओर अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले विमानों के यात्री एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे। उनकी सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टनगर डिपो से अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन अमौसी भेजी गई। जिससे एयरपोर्ट से उतरे यात्रियों ने सफर किया। दूसरी ओर मुंशीपुलिया से जाने वाली मेट्रो को रेलखंड से हटाने के बाद रूट की अन्य मेट्रो संचालित हुईं, जिससे यात्रियों ने सफर किया। मेट्रो जनसंपर्क विभाग ने बताया कि ब्रेक फेल होने से असुविधाएं हुईं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो का संचालन अधिक बाधित नहीं हुआ। पंद्रह मिनट तक करना पड़ा इंतजार अमूमन मेट्रो चार से पांच मिनट में स्टेशनों पर उपलब्ध हो जाती है। लेकिन सोमवार दोपहर एक मेट्रो के ब्रेक फेल होने से दिक्कतें हुईं, जिससे रूट की अन्य मेट्रों को स्टेशन तक पहुंचने में पंद्रह से बीस मिनट लगे। आईटी मेट्रो स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री गोविंद पांडेय ने बताया कि उन्हें कानपुर जाना था। मेट्रो के देर से आने के कारण उन्हें दिक्कतें हुईं।

संक्षिप्त

मलिहाबाद रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम, एंबुलेंस फंसी

संवाददाता

लखनऊ। मलिहाबाद के अमानीगंज रेलवे फाटक पर सोमवार दोपहर लंबा जाम लग गया। फाटक बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह घटना दोपहर के व्यस्त समय में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रेलवे फाटक अपेक्षा से अधिक समय तक बंद रहा, जिससे लखनऊ–हरदोई मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जाम में निजी वाहनों, बाइकों, ऑटो और मालवाहक गाड़ियों के साथ एक एंबुलेंस भी फंस गई।

एंबुलेंस के फंसे होने से लोगों में चिंता बढ़ गई और उसे निकलने में काफी समय लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमानीगंज रेलवे फाटक पर ऐसी स्थिति अक्सर बनती है। ट्रेन गुजरने के बाद भी फाटक देर से खुलने और उचित यातायात व्यवस्था न होने के कारण नियमित रूप से जाम लगता है। इससे स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। काफी देर बाद फाटक खुलने पर यातायात धीरे–धीरे सामान्य हो सका। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और रेलवे विभाग से मांग की है कि फाटक पर यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके।

बिजली कार्मिको का प्रांतव्यापी विरोध प्रर्दशन 400 दिन के करीब

साल के पहले दिन होगा विरोध दिवस

संवाददाता

लखनऊ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में एवं निजीकरण के फलस्वरुप चल रहे आंदोलन के दौरान पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों तथा बिजली कर्मचारियों के निवास पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आज लगातार 397 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों में व्यापक विरोध ा प्रदर्शन जारी रखा और आगामी 01 जनवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की।

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर अखिलेश यादव का आया पहला बयान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या की नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के नंदननगर के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा को नौ दिसंबर को देहरादून में एक समूह ने कथित रूप से नस्लीय अपशब्द कहे, जिसका विरोध करने पर उसपर हमला कर दिया गया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, यादव ने कहा कि "विघटनकारी सोच रोज

किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फलफूल रहे हैं।" उन्होंने दावा किया कि इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता–अखंडता खतरे में है। अखिलेश यादव ने कहा, "आज इन हिंसक हालात में यही बात सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम सब शान्ति प्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें, नहीं तो हममें से कोई भी कल इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा।" सपा प्रमुख ने शीर्ष अदालत से अपील करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे।

मुंह में लौंग, सुपारी दबाकर सोने की आदत बन सकती है जानलेवा'

अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जटिल प्रक्रिया द्वारा निकाली फेफड़ो में फँसी सुपारी, बचाई मरीज की जान'

संवाददाता

लखनऊ। मुंह में सुपारी, लौंग या कोई और चीज रखकर सो जाना कई लोगों की आदत होती है लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। नींद के दौरान कई बार इस तरह की चीजें सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंच सकती हैं और लंबे समय तक बार–बार होने वाले संक्रमण का कारण बन सकती हैं। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिल जहां करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को बार–बार छाती में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत के साथ अस्पताल में आई। हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे आई सी यू में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान एक्स–रे और सीटी स्कैन की जांच में उनके फेफड़ों में निमोनिया पाया गया। मरीज को पहले से हृदय संबंधी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर था और वह ब्लड थिनर (खून पतला करने की दवाएं) भी ले रही थीं। बीमारी के कारण को समझने के लिए डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी करने का निर्णय लिया। अपोलो हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ शुभम अग्रवाल ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी के दौरान यह देखा गया कि जिस हिस्से में निमोनिया था, वहां फेफड़े के अंदर कोई वस्तु फंसी हुई है। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि उस वस्तु को निकालना बेहद जरूरी है और इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। प्रक्रिया लंबी होने के कारण परिवार पहले घबरा गया लेकिन बातचीत और समझाने के बाद उन्होंने सहमति दी। इसके बाद मरीज को पूरी तरह बेहोश कर फेफड़ों के अंदर कैमरे और विशेष उपकरण की मदद से वह वस्तु बाहर निकाली गई। प्रक्रिया के दौरान हल्की ब्लीडिंग हुई, जिसे दवाओं से नियंत्रित कर लिया गया। जब वह वस्तु बाहर निकाली गई, तो वह सुपारी का एक टुकड़ा था। परिवार ने बताया कि मरीज को सुपारी चबाने की आदत थी और वह कई बार रात में भी मुंह में सुपारी रखकर सो जाती थीं। यही सुपारी का टुकड़ा उनके फेफड़ों में फंसा हुआ था और उसी की वजह से उन्हें लंबे समय से बार–बार संक्रमण हो रहा था। सुपारी का टुकड़ा निकालने के बाद मरीज की हालत तेजी से सुधरी, उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया और कुछ ही समय में वह स्वस्थ होकर घर लौट गईं। डॉ शुभम ने कहा कि जब कोई बाहरी चीज सांस के रास्ते फेफड़ों में फंस जाती है, तो उसके आगे का पूरा हिस्सा संक्रमित हो जाता है और वहां मवाद बन सकता है। कई बार व्यक्ति के गहरी नींद में होने पर सांस की नली से फेफड़े में जाकर फंसी चीजों का पता भी बस हल्की खांसी से नहीं चल पाता है। खांसी की दवा या नेब्यूलाइजर के इस्तेमाल से कई बार ये लक्षण भी धीमे पड़ जाते हैं और एक्स रे से पता भी नहीं चल पाता कि फेफड़े में कुछ फंसा है। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डॉक्टर शुभम ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुंह में सुपारी, लौंग या कोई भी चीज रखकर सोता है तो यह बेहद खतरनाक है, ये आदत जान के लिए खघ्तरा हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी वयस्क को बार–बार छाती का संक्रमण या निमोनिया हो रहा है, तो यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कोई बाहरी वस्तु फेफड़ों में तो नहीं फंसी है। नींद में ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति को खांसी के जरिए भी इसका साफ संकेत नहीं मिल पाता, जिससे असली कारण लंबे समय तक छुपा रह जाता है। डॉ. मयंक सोमानी, एमडी और सीईओ, अपोलोमेडिक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कहा कि यह केस बताता है कि रोजमर्रा की छोटी और लापरवाही भरी आदतें जैसे रात में कुछ चबाते हुए सोना गंभीर बीमारी का कारण बन सकती हैं। फेफड़ों में फंसी बाहरी वस्तु लंबे समय तक बिना साफ लक्षण के संक्रमण फैलाती रहती है और इलाज केवल दवाओं तक सीमित रह जाता है। समय पर सही जांच और इलाज से न सिर्फ बीमारी की असली वजह भी सामने आई, बल्कि मरीज की जान बची। इसलिए बार–बार होने वाली खांसी या संक्रमण के पीछे छिपे कारणों की गहराई से जांच जरूरी है।

यूपी बना देश में सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य

महाकुंभ में आये 66 करोड़ पर्यटक, 137 करोड़ पर्यटकों के आगमन से यूपी देश में प्रथम
काशी, अयोध्या और प्रयागराज बने देश में फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य पर्यटन विभाग ने 2025 में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। मुख्यमंत्री के विजन के मुताबिक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के नवीनीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विकास से यूपी घरेलू पर्यटन में देश में प्रथम तथा विदेशी पर्यटन में चौथा स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि 3.66 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा की। इसकी बड़ी वजह प्रयागराज में दिव्य–भव्य महाकुंभ–2025 रहा, जहां रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा–वृंदावन और श्रावस्ती जैसे स्थल अब देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुके हैं। सीएम योगी के विजन के मुताबिक प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म की नई संभावनाओं का विकास हुआ है, पर्यटन एवं कला, संस्कृति विभाग द्वारा होने वाले दीपोत्सव, रंगोत्सव, देवदीपावली और माघ मेला जैसे आयोजन देश, विदेश के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गये हैं। उत्तर प्रदेश, भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन 2017 से पूर्व की सरकारों में उपेक्षित पड़े पर्यटन स्थलों को सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन काल में न केवल पुनर्जीवित किया, परिवहन, हॉस्पिटैलिटी और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया। एयरपोर्ट, ट्रेन–बस सेवाओं तथा होटल–होम स्टे की सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पर्यटन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 1283.33 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कीं। जिनमें वाराणसी के घाटों का सौंदर्यीकरण, एकीकृत सर्किट हाउस और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, चित्रकूट में कालिंजर एकीकृत मार्ग तथा राम वन गमन मार्ग पर पर्यटक सुविधा केंद्रों का विकासप्रमुख हैं। मुरादाबाद के भगवानपुर मंदिर,शाहजहांपुर के अजीताश्रम योगकुंज जन्मस्थली, वाल्मीकिनगर में लवकुश कुटी, त्रेतायुग भूमि कुटी, भरतकोठी, सीता रसोई और कौसल्या स्थल का जीर्णोद्धार तेजी से हो रहा है। जिला पर्यटन इकाइयों के माध्यम से 7 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई परियोजनाएं प्रारंभ हुईं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहयोगिता योजना में इस वर्ष 2 परियोजनाओं को अनुमोदन मिला, जबकि 4 अन्य को जल्द ही स्वीकृति मिलने वाली है।पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर समय–समय पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया, जिसने प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इस क्रम में इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में महाकुम्भ–2025 का आयोजन रहा। महाकुम्भ के दिव्य–भव्य आयोजन में देश विदेश से रिकार्ड संख्या में पर्यटक प्रयागराज आये। आयोध्या के भव्य दीपोत्सव के आयोजन में दीयों के प्रज्जवलन का अपना ही पुरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं वाराणसी की रामलीला में विश्व का सबसे बड़ा राम तख्त भी गिनीज बुक में दर्ज हुआ। गंगा घाट पर राम कथा, कथक–नृत्य, 3–डी होलोग्राम और प्रोजेक्शन मैपिंग ने समा बांधा। वहीं होली पर ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव, रामनगर की चिल्का होली, काशी की होली तथा मथुरा की लठमार होली ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया। 2025 में घाघरा महोत्सव, ब्रह्मा महोत्सव, मकर संक्रांति महोत्सव, दूधई मेला, गाजीपुर महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, चित्रकूट का लालगढ़ मेला जैसे आयोजनों से पर्यटक संख्या, राजस्व और स्थानीय रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 ने प्रदेश में पर्यटन के बहुआयामी विकास किया। नच–जवनतपेउचवतजंस.पद पर 1757 पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 37,688. 58 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर्यटन विभाग ने यूपी के टूरिज्म के प्रचार–प्रसार के लिए ज्यूरिख ट्रेवल मार्ट, ग्लोबल ट्रेवल मार्केट–2025, पेरिस फैशनवीक, जीटीएसी टोक्यो–सिडनी, आईटीबी एशिया, फिटूर–2025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर आईटीबी इंडिया, जीटीए पटना–लखनऊ–मुंबई–चेन्नई–दिल्ली, एक्सपो जयपुर आदि में भागीदारी से प्रचार बढ़ा।युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पर्यटन विभाग विभाग ने सीएम टूरिज्म फेलाशिप प्रोग्राम का संचालन किया गया।

संक्षिप्त

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गहन जांच की मांग, बिना साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के प्रीपेड मोड में बदले गए लाखों मीटर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर गंभीर अनियमितताएँ सामने आ रही हैं। 22 दिसंबर तक प्रदेश में कुल 56 लाख 82 हजार 784 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 37 लाख 43 हजार 612 मीटर उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं।भारत सरकार के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट (एस0ए0टी) किया जाना अनिवार्य है। यह टेस्ट पूरा होने के बाद ही यह प्रमाणित होता है कि मीटर एमडीएम सहित सभी तकनीकी मानकों पर सही तरीके से कार्य कर रहा है। इसी के बाद ओपेक्स मॉडल के तहत मीटर लगाने वाली कंपनी को मासिक भुगतान शुरू किया जाता है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न बिजली कंपनियों द्वारा अब तक केवल 34 लाख 32 हजार 806 स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का ही साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा किया गया है।

ज्योतिषी का संबंध किसी जाति या धर्म से नहीं : शाहजी महाराज

संवाददाता

लखनऊ। जिस तरह अभिनय के क्षेत्र में ऑस्कर या फिल्मफेयर अवार्ड का अपना बड़ा नाम होता है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा सम्मान कार्यक्रम आयोजित होता है जिसके लिए देश–विदेश से लोग आते हैं और यह सम्मान यूं ही नहीं मिल जाता इसके लिए डॉ अजीज सिद्दीकी, डॉ रीमा सिंह और उनकी पूरी टीम, समाज हित में लोगों के द्वारा किए गए कार्यों पर पैनी नजर रखते हुए उनका चयन करती है। प्रति वर्ष 25 दिसंबर को किए जाने वाले अटल सम्मान का सिलसिला लगातार व्यापक होता जा रहा है और इस वर्ष ज्योतिषाचार्य एक ऐसा सम्मान दिया गया जो चर्चा का विषय बन गया। भविष्यवक्ता शहनवाज शाहजी महाराज जिन्होने समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद की मुहिम के चलते कहीं ना कहीं उनके हाथों की लकीरों और सितारों की गर्दिशों के तालमेल के अध्ययन से एक ऐसा तंत्र तैयार किया है जिससे समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। हस्तरेखा विज्ञान, जन्म कुंडली और रत्नों के ज्ञान को सीखने के बाद शाही जी समाज के सभी धर्म के लोगों को अपनी प्रतिभा और ईश्वर की रहमत से मिले अदभुत चमत्कार को समाजसेवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस काम को करने में उन्हें दुश्वारियां नहीं आई अपने ही समाज के लोगों से कई तरह की बातें भी सुनाई गयी लेकिन शाहजी का कहना है कि ज्योतिषी का संबंध किसी जाति या धर्म से नहीं हो सकता बल्कि कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत से है जिसके बारे में स्वयं मुस्लिम धर्म ग्रंथो में उल्लेख किया है और कुछ अदृश्य ताकतों का साथ में होने से उनके काम और ज्ञान में भरपूर मदद मिलती है। शाहजी द्वारा रत्न ज्योतिष के अनुसार इन्सानों के दोष के साथ साथ उनके रोगों को भी दूर करने के काम में प्रयासरत है और उन्होने बताया कि आयुर्वेद में भी रत्नों की भस्म द्वारा रोग निवारण के अनेक प्रयोग बताए गए हैं और इसका वैज्ञानिक कारण रत्न में उपस्थित विशेष रासायनिक तत्व हैं।

जिला पंचायत बोर्ड बैठक में हंगामा, अपर मुख्याधिकारी पर रिश्वतखोरी के आरोप

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक उस वक्त हंगामेदार हो गई, जब जिले भर से आए जिला पंचायत सदस्यों ने नक्शा स्वीकृति और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैठक के दौरान सदस्यों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर नारेबाजी की और अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे के खिलाफ हल्लाबोल किया। हालात इतने बिगड़े कि बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। जिला पंचायत की इस बोर्ड बैठक में लगभग सभी क्षेत्रों से पहुंचे जिला पंचायत सदस्य एकजुट नजर आए। सदस्यों का कहना था कि जिला पंचायत कार्यालय में नक्शा स्वीकृति से लेकर विकास कार्यों तक हर स्तर पर रिश्वतखोरी व्याप्त है। आरोप लगाया गया कि बिना लेन–देन के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं और आम जनता के काम जानबूझकर रोके जाते हैं।

बैठक के दौरान सदस्यों ने सीधे तौर पर अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे को निशाने पर लिया। सदस्यों का आरोप था कि उनके संरक्षण में जिला पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार फल–फूल रहा है। सदस्यों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार बढ़ते विरोध और हंगामे के बीच बोर्ड बैठक में अपर मुख्याधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे जिला पंचायत कर्मियों का वेतन रोके जाने का निर्णय भी लिया गया। सदस्यों का कहना था कि जब तक निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह कदम जरूरी है। यह पूरी बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव भी मौजूद रहे और वे अध्यक्ष के बगल की कुर्सी पर बैठे नजर आए।

प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से हो रहे हैं समृद्ध

बीज निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे आधुनिक कृषि यंत्र
इस वित्तीय वर्ष में अब तक 882 किसानों को मिला आधुनिक कृषि यंत्र
किसान विकसित भारत विजन की परिकल्पना की ओर हो रहे अग्रसर

बीएनई

रायपुर। प्रदेश के किसान खेती–किसानी में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। वहीं विकसित भारत विजन की परिकल्पना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में किसान लाभ ले रहे हैं। किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर खेती किसानी के उन्नत एवं आधुनिक तौर तरीके अपना रहे हैं, जिससे किसानों को पारंपरागत किसानी से अधिक फायदा हो रहा है। शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्र किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं जिनसे किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो उन्नत बीज हो या अन्य विभागीय योजनाएं। इसी क्रम में बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों के हित में शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत किस्म में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है स खेती किसानी के विभिन्न चरणों जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई जैसे सभी चरणों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र किसान के द्वारा चयन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। बीज निगम द्वारा किसानों को शक्ति चलित कृषि यंत्र जैसे – रोटावेटर, स्व चलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, पावर वीडर, मल्चर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों को समय की बचत के साथ–साथ श्रम लागत में भी कमी हो रही है। किसानों का कहना है कि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से खेती का कार्य कम समय में और अधिक सटीक तरीके से हो पा रहा है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई है। परिणाम स्वरूप बाजार में उन्हें उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। 882 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों से किया गया लाभान्वित बता दें कि बीज निगम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। निगम द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित है। जिससे कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिल रहा है। वर्ष 2025–26 में अभी तक 882 किसान को अनुदान पर कृषि यंत्रों से लाभान्वित हो चुके हैं। स्व–चलित रीपर से कटाई हुई आसान बिलासपुर जिले के किसान नारायण दल्लू पटेल ने बीज निगम के माध्यम से अनुदान पर स्व–चलित रीपर प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पहले एक एकड़ फसल की कटाई में 10–12 मजदूर और पूरा दिन लगता था, जबकि अब वही कार्य 2–3 घंटे में पूरा हो जाता है। इससे कटाई लागत में 50–60 प्रतिशत तक कमी आई है और समय पर कटाई संभव हो सकी है। रोटावेटर से खेत की तैयारी हुई तेज रायपुर जिले के किसान हीरालाल साहू ने बताया कि रोटावेटर के उपयोग से खेत की जुताई एक ही बार में हो जाती है। पहले जहाँ खेत तैयार करने में 3–4 दिन लगते थे, अब कुछ घंटों में कार्य पूर्ण हो जाता है। इससे फसल उत्पादन में 20–25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। सीड ड्रिल से बीज की बचत और बेहतर उत्पादन खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले के किसान लेखूराम छेदईया ने अनुदान पर सीड ड्रिल मशीन क्रय किए है। उन्होंने बताया कि इस मशीन का प्रयोग बोआई में करने पर बीज की 15–25 प्रतिशत तक बचत होती है। समान दूरी और गहराई पर बोआई से अंकुरण बेहतर हुआ है और उत्पादन में 20–30 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई।

एनसीएल में महिला खेलकूद प्रतियोगिता 'निरामया 2.0' का हुआ भव्य शुभारंभ

बीएनई

सिंगरौली। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीईटीआई परिसर में सोमवार को दो दिवसीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 'निरामया 2.0' का शुभारंभ हुआ। एनसीएल परिवार की महिलाओं की प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सिलोस प्रेसिडेंट एवं कृति महिला मंडल की अध्यक्षा बी.के. दुर्गा ने वीसी के माध्यम से किया। इस अवसर पर कृति महिला मंडल की उपाध्यक्षा नम्रता कुमार, संगीता नारायण, वीणा सिंह, शीला द्विवेदी, रूबी जायसवाल सहित महिला मंडल की अन्य सदस्याएं उपस्थित रहीं। 'निरामया 2.0' के अंतर्गत बैडमिंटन, कैरम, लूडो, 50 मीटर दौड़, कबड्डी, रिले रेस, रस्साकशी एवं बैलेंस द ग्लास जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पाँच टीमों के लगभग 45 प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। यह खेलकूद प्रतियोगिता गृहिणियों एवं एनसीएल परिवार की महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ–साथ नारी सशक्तिकरण एवं महिला चेतना की दिशा में एनसीएल के सतत प्रयासों को भी रेखांकित करती है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह एवं खेल भावना देखने को मिल रही है। इस दो दिवसीय प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को सिंगरौली स्टेडियम में किया जाएगा।

कॉरपोरेट सब्सक्राइबर्स को 80% तक निकासी की छूट, रिटायरमेंट होगी ज्यादा आसान

एजेंसी

नई दिल्ली। नए नियमों के अनुसार, गैर–सरकारी सब्सक्राइबर्स अब रिटायरमेंट के समय 12 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस का 80: तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं जबकि शेष 20: राशि एन्युटी के रूप में दी जाएगी। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा। वे केवल 60% तक की निकासी कर पाएंगे और शेष 40: राशि एन्युटी के रूप में रखनी होगी। इस संशोधन से पहले, सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए 60: एकमुश्त निकासी और 40% एन्युटी का नियम अनिवार्य था। 8 लाख से कम कॉर्पस होने पर नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी गैर–सरकारी सब्सक्राइबर ने योगदान के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, तो 8 लाख रुपये या उससे कम का कॉर्पस होने पर वह पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है। 12 लाख रुपये से अधिक कॉर्पस होने पर 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीचरू यदि संचित राशि 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है तो अधिकतम 6 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं और शेष राशि का उपयोग एन्युटी के लिए किया जाएगा। 12 लाख से अधिकरू यदि कॉर्पस 12 लाख रुपये से अधिक है तो सब्सक्राइबर्स अब 60:40 के बजाय 80:20 (एकमुश्त बनाम एन्युटी) का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स अब 85 वर्ष की आयु तक निवेशित रह सकते हैं, जब तक कि वे खुद पहले बाहर निकलने का विकल्प न चुनें। अन्य महत्वपूर्ण नियम 15 वर्ष के योगदान के बाद या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जो भी पहले हो) सामान्य निकासी की अनुमति है। यदि एन्युटी खरीदने या एकमुश्त निकासी से पहले सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो कुल संचित राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को दी जाएगी। यदि कोई सब्सक्राइबर लापता है और उसे मृत मान लिया गया है।

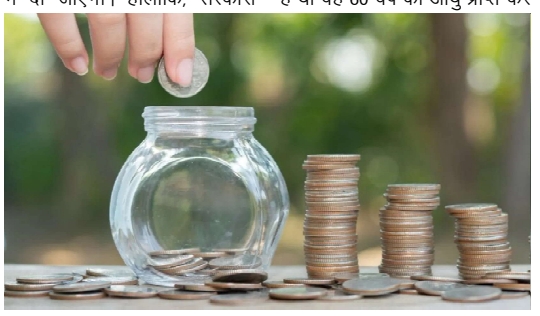

पीएम मोदी ने कोनेरु हम्पी और अर्जुन एरिगैसी को दी बधाई, विश्व रैपिड चौंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहा में फिडे विश्व रैपिड चौंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को सोमवार को बधाई देते हुए उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। हम्पी ने मौजूदा चौंपियन के रूप में इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। वह रविवार को समाप्त हुई प्रतियोगिता के अंतिम दौर के बाद 8.5 अंक लेकर दो अन्य ग्रैंडमास्टर्स के साथ संयुक्त बढ़त पर थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) के टाईब्रेक नियमों के कारण उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।मोदी ने एक्स पर लिखा, ''दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चौंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली कोनेरू हम्पी को हार्दिक बधाई। खेल के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं।''पीएम मोदी ने अर्जुन एरिगैसी को भी जीत की बधाई दी। कहा कि दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड शतरंज चौंपियनशिप के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी पर गर्व है। उनका दृढ़ संकल्प सराहनीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री भारतीय खिलाड़ियों का लगातार हौसला बढ़ाते रहते हैं और उनमें से कई खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं। अगर हम्पी रविवार को खिताब जीत जातीं तो वह तीन विश्व रैपिड खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन जातीं। इससे पहले उन्होंने 2019 और 2024 में खिताब जीते थे। ओपन वर्ग में अर्जुन एरिगैसी ने कांस्य पदक जीता। वह विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और रूस के ग्रैंडमास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमिएव के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे। अब यह खिलाड़ी विश्व ब्लिट्ज टूर्नामेंट में भाग लेंगे।

संक्षिप्त

अभिषेक शर्मा की नजर भारतीय वनडे टीम में जगह बनाने पर? विजय हजारे ट्रॉफी को बनाया मंच

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा अब खुद को सिर्फ छोटे प्रारूप तक सीमित नहीं रखना चाहते। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके अभिषेक अब 50 ओवर के क्रिकेट में भी चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के मिशन पर हैं। विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) उनके लिए वह मंच बन सकती है, जहां से वह वनडे टीम इंडिया में अपनी दावेदारी को मजबूती दे सकें। ट्रेनिंग सेशन में दिखा साफ इरादा रविवार को पंजाब टीम के ट्रेनिंग सेशन के दौरान अभिषेक शर्मा का इरादा और सोच दोनों साफ नजर आए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही वह नेट्स में बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने साथी खिलाड़ी गौरव चौधरी से एक सवाल पूछा, श्फील्ड क्या है?श यह सवाल किसी वास्तविक मैच का नहीं, बल्कि एक काल्पनिक फील्ड प्लेसमेंट को लेकर था। इसका जवाब मिला, श्मिड–ऑफ सिंगल बचाने के लिए रखा है।श इस छोटी–सी बातचीत ने ही बता दिया कि अभिषेक नेट्स में भी खुद को मैच जैसी स्थिति में ढालकर तैयारी कर रहे हैं।

एनसीएल में 'कोल हैंडलिंग प्लांट' के रखरखाव व स्वच्छता अभियान उपरांत हुआ पारितोषिक वितरण समारोह

स्वच्छता से सुरक्षा और समृध्दि की ओर थीम पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

बीएनई

सिंगरौली। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के मुख्यालय में सोमवार को कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी) के रखरखाव एवं स्वच्छता अभियानश के निरीक्षण उपरांत विजेताओं को सम्मानित करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी थीम 'स्वच्छता से सुरक्षा और समृद्धि की ओर' थीम पर आधारित थी । 22 से 25 दिसंबर 2025 तक चले निरीक्षण अभियान में एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं के सीएचपी को 4 भागों में बांटा गया था व कोल स्पीलेज, धूलशमन व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग), पीपीई का उपयोग, उपयोग, विद्युत सुरक्षा, अर्थिंग, एवं कंट्रोल रूम की स्वच्छता जैसे कई पैमानों पर अंक देकर पुरस्कृत किया गया।

समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एनसीएल के सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) बी. साईराम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में एनसीएल के निदेशक (कार्मिक) मनीष कुमार, निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण, निदेशक (तकनीकी/संचालन) सुनील प्रसाद सिंह, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) आशुतोष दिवेदी और मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय कुमार जायसवाल, श्रमिक संघ प्रतिनिधियों में आरसीएसस से लाल पुष्पराज सिंह, बीएमएस से श्यामधर दुबे और सीएमओएआई से एस.के. पांडे उपस्थित रहे। सभी परियोजनाओं के महाप्रबंधकगण, मुख्यालय के विभागाध्यक्ष एवं परियोजनाओं से एसओ ईएंडएम, सीएचपी इंचार्ज और सीएचपी से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही सीएचपी की देखरेख करने वाली संविदा कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। एनसीएल में कोल हैंडलिंग प्लांट के रखरखाव एवं स्वच्छता अभियान उपरांत आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चेयरमैन, कोल इंडिया लिमिटेड बी. साईराम ने एनसीएल की इस पहल को 'मील का पत्थर' बताते हुए कहा कि यह कोल इंडिया की अन्य अनुषंगियों के लिए प्रेरणा व जागरूकता का माध्यम बनेगी। उन्होंने परिचालन दक्षता, ऊर्जा खपत में कमी और डिजिटलीकरण को बल देते हुए इस अभियान को निरंतर जारी रखने का आह्वान करते हुए दोहराया कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर एनसीएल के निदेशकमंडल व मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएचपी रखरखाव एवं स्वच्छता अभियान परिचालन दक्षता, अनुशासन, सुरक्षा और 'जीरो हार्म' संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नियमित निरीक्षण व फॉलो–अप के माध्यम से उच्च मानकों को निरंतर कायम रखने, हरित माध्यम से कोयला प्रेषित करने हेतु सीएचपी की उपयोगिता बढ़ाने, तथा भविष्य में एनसीएल के लक्षित सीएचपी से प्रेषण को समयबद्धता के साथ हासिल करने का आह्वान किया । पारितोषिक वितरण समारोह मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएचपी और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया:

श्रेणी–1 (नई एफएमसी): दुधिचुआ (नई) सीएचपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जयंत (नई) सीएचपी द्वितीय और अमलोरी आरएलएस तृतीय स्थान पर रहे।

श्रेणी–2 (आउटसोर्सिंग सीएचपी): खड़िया फेज–II सीएचपी ने प्रथम पुरस्कार जीता। ब्लॉक–बी (द्वितीय) और कृष्णाशिला (तृतीय) स्थान पर रहे।

श्रेणी–3 (विभागीय < 5MTPA): बीना सीएचपी ने प्रथम, ककरी ने द्वितीय और खड़िया फेज–I ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

श्रेणी–4 (विभागीय > 5MTPA)+ अमलोरी सीएचपी ने प्रथम स्थान हासिल किया। निगाही और दुधिचुआ (पुरानी) सीएचपी संयुक्त रूप से दूसरे, जबकि जयंत (पुरानी) सीएचपी तीसरे स्थान पर रही। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट कार्य करने वाले संविदा कर्मियों जितेंद्र यादव, प्रमोद चौरसिया, संतोष वर्मा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ईएंडएम विभाग की ओर से निरीक्षण के दौरान देखी गई सर्वोत्तम् प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (ईएंडएम) दिनेश दंडोतिया एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।

22 साल की कृति सेनन ने चीख-चीखकर मांगी मदद, एक्ट्रेस के पहले ऑडिशन का वीडियो हुआ वायरल

एजेंसी

कृति सेनन की गिनती मौजूदा वक्त की टॉप लीडिंग एक्ट्रेस में होती है। उनके पास फिल्मों की कतार लगी हुई है। हाल ही में धनुष के साथ 'तेरे इश्क में' में नजर आईं कृति अब शाहिद कपूर के साथ 'कॉकटेल 2' में दिखाई देंगी। इस बीच सोशल मीडिया पर कृति सेनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कई साल पुराना है, जिसमें कृति अपना पहला ऑडिशन देते नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृति का पहला ऑडिशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कृति सफेद रंग की स्लीवलेस वन पीस में नजर आ रही हैं। बहुत हल्के मेकअप के साथ कृति कैमरे के सामने अपने प्रोफाइल के बारे में बता रही हैं। हाथ में कृति एक बोर्ड पकड़े हैं, जिस पर उनके बारे में लिखा है। इसमें कृति सेनन का नाम, उम्र, लंबाई और शूटिंग की डेट्स लिखी हुई हैं। इसके साथ ही उनके बारे में भी लिखा है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें तैराकी आती है और अभी तक उन्होंने कोई भी एड तक शूट नहीं किया है। ऑडिशन में कृति ने की ऐसी एक्टिंग वीडियो में अपना प्रोफाइल बताते हुए कृति अपना परिचय देती हैं। एक्शन बोलने के बाद मुस्कुराते हुए कृति सेनन अंग्रेजी में अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताती हैं। हाय, मैं कृति सैनन हूं। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी लंबाई 5श्9 है। ये है मेरी प्रोफाइल, इसके बाद वो अपनी लेफ्ट–राइट प्रोफाइल दिखाती हैं। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या वे ऑडिशन की बताई गई तारीखों पर उपलब्ध हैं, जिस पर वे हां में जवाब देती हैं। वो बताती हैं कि इससे पहले उन्होंने किसी ब्रांड का कोई एड नहीं किया है। फिर वो बताती हैं कि हां, उन्हें तैराकी आती है, लेकिन वो टू पीस कपड़ों में सहज नहीं हैं। इसके बाद कृति एक सीन करती हैं, जिसमें वो हेल्प–हेल्प चिल्लाती हैं और खुद को बचाने की एक्टिंग करती हैं। इसमें वो अलग–अलग तरह की सिचुएशन में मदद मांगने की एक्टिंग करती हैं। 'हीरोपंती' से की अपने करियर की शुरुआत कृति सेनन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म 'हीरोपंती' से की थी। इसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। ये फिल्म सफल रही थी और कृति के अभिनय को भी पसंद किया गया था। इसके बाद कृति सेनन कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहीं।

बैटल ऑफ द सेक्सेस में किर्गियोस की जीत : सबालेंका को हराया, बदले नियमों को लेकर टेनिस जगत में बहस तेज

एजेंसी

दुबई। रविवार को दुबई में खेले गए एक हाई–प्रोफाइल प्रदर्शनी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने महिला विश्व नंबर–एक आर्यना सबालेंका को श्बैटल ऑफ द सेक्सेसश में 6–3, 6–3 से हरा दिया। यह मुकाबला टेनिस प्रशंसकों के बीच पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें नियमों में बदलाव किए गए थे। हालांकि, इस मैच की तुलना 1973 के ऐतिहासिक मुकाबले से करना मुश्किल माना जा रहा है। 1973 का ऐतिहासिक संदर्भ 1973 में बिली जीन किंग और बॉबी रिग्स के बीच हुआ मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि महिला टेनिस की पहचान और समान पुरस्कार राशि की लड़ाई का प्रतीक था। उस समय बिली जीन किंग ने 55 वर्षीय रिग्स को 6–4, 6–3, 6–3 से हराकर इतिहास रच दिया था। वह मुकाबला महिला प्रोफेशनल टूर की वैधता और सम्मान के लिए बेहद अहम था। बदले नियमों में खेला गया मुकाबला दुबई में हुए इस प्रदर्शनी मैच में दोनों खिलाड़ियों के लिए नियम अलग थे। दोनों खिलाड़ियों को सिर्फ एक सर्व की अनुमति थी सबालेंका के कोर्ट का आकार नौ प्रतिशत छोटा कर दिया गया, ताकि किर्गियोस की ताकत और रफ्तार को संतुलित किया जा सके इन नियमों की वजह से कुछ फैंस ने मैच को मनोरंजक बताया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743